HRA an Usia, The Gazette of India,

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1998 (माघ 4, 1919)

No. 41

NEW DELTH, SATURDAY, JANUARY 24, 1998 (MAGHA 4, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग रंकलन के रूप में रक्षा का सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-मुची भाग II--बण्ड 3---उपसप्त (lij)--भारत सरकार के मंद्रालयों पृष्ठ ξž माग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत मरकार के (जिनमें रहा मंत्रालय भी ग्रामिल है) और मंत्रालयों भीर उच्चतम न्यायालयों द्वारी जारी केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ सासित क्षेत्रों के की गई विधितर नियमों, विनियमों, बादेशों प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी कए गए तथा संकट्यों से संबंधित पश्चिमुचनाएं 55 सामाण्य सांविधिक नियमों और सांविधिक भाग I--वण्डं 2-- (रक्षा मंत्राजय को छोबकर) भारत सरकार मावेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां के मंत्रालयों और उच्चतम म्यायालय द्वारा भी मामिल है) के हिन्दी प्राधिकत पाट (ऐसे जारी की गई सरकारी अधिकारियों की पाठों की छोड़कर जो भारत के राजपक्ष के तिथुक्तियाँ, पदोन्नतियों, खुड्रियों भावि के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) संबंध में आंध्रसूचनाएं . 85 मान !-- अभ 3-- रक्षा मवाल्य द्वारा जारी किए गए संकल्पों मान 🏗 -- बण्ड ४ -- रक्षा मंश्रालय द्वारा जारो किए वए सोविधिक और प्रसाविधिक भावेशों के संबंध में प्रसि-नियम और प्रावेश : सूचमाएं . . माग∐...-अर्था...--उच्च न्यायालयौ, निश्चक और महालेखा-जारा I--वन्ध 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी परीक्षक, मंच लोक सेना प्रायोग, रेल विभाग मधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतिसों, और मारत मरकार से सबद्ध और प्रधीनस्थ छुट्टियों भाषि के संबंध में ध्रधिसूचनाएं . 133 कार्यातयों द्वारा जा कि निर्धि सिधिसूचना . 53 माप 11--खण्ड 1--मधिनियम, मध्यावेश और विनियम . भाग II-वण्ड- 1क -- मधिनियमीं, मध्यावेशीं और विनियमीं का भाग III - अग्र 2 - रेडेंट कार्मालय द्वारा जारी की गई पेटेक्टों हिन्दी भाषा में प्राधिकत पाठ और डिकाइमों से संबंधित प्रधिस्वनाएं भाग II--बाब्ड 2--विश्लेयक तथा विश्लयको पर प्रवर समितियो और नोटिस 147 के विल तथा रिपोर्ट मार [[[--वान्त 3--मन्य भापूननों से प्राधिकार के अधीन भाग II - -वावड 3--- अव-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों अधवाद्वारा जारी की गई प्रक्षित्वनाएं . (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणीं (संध भासित क्षेत्रों के प्रकासमों माग III — बण्ड 4—विविध भिक्षसूचनतर् जिनमें साविधिक को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य निकारी द्वारा जारी की गई प्रधियुजनाए, साविधिक नियम (जिसमें सामाग्य स्वरूप षावेश, विज्ञापन और नाटिस शामिल हैं। 421 के शावेश और उपनिधियां झावि भी शामिल हों)।् साग IV-गैर-परकारी व्यक्तियों और गैर-परकारी निकार्यों भाग II--वाण्ड 3--उप-वाण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयी द्वारा आरो किए गय विद्वापन और (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय नोटिस . 11 प्राधिकरणों (सब सासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोंब्हर) बारा जारी किए गए सर्विधिक माग V---अंग्रेजी और हिम्बी दोनों में अल्म और मादेश और मधिपुचनाएं भाककों को बताने नाल। सम्पूरक

CONTENTS

, '	#DA		PAGE
PART I.— Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAR	r II—Section 3—Sus-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general char eter) issued by the Ministries of the Government of	
PART I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the		India (including the Ministry of Defences and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
Supreme Court	85 PAS	T II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
by the Ministry of Defence PART I —Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of	1 Рав	r III—Section)—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Rallways and by Attached and Subordinate	•
Defence	. 133	Offices of the Government of India	, 53
PART II SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regu- lations	* РАЧ	r III - Section 2-Notifications and Notices is sued by the fitent Office, relating to Patents and Designs	147
PART II —Section 2 —Bills and Reports of the Select Committee on Bills	PAR	TIII—Section 3 -Notifications issued by or under the authority of Chief Commis- sioners	-
PART II -SECTION 3 -SUB-SECTION (I) -General Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	PAD	ir III -Section 4 Miscellaneous Notifications including Notifications; Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	 421
PART II SECTION 3—Sug-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Contral Authorities (other than the Administration of Union Territories)		Private Individuals and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies. RT V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi	11

भाग 1—खण्ड 1 । [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्तर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिस्वनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नद्रं विल्ली, विनांकं 4 ज्लाई 1997

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू-भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एम्री का अतिक्रमण करले हुए पूर्वी हिमालय क्षेत्र (जीन-2) से संबंधिक योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के फूष्ण जलवाय अंत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इस के यूनिट को सहायता दोने के लिए पूर्विक्ति किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवी पंचवर्षीय योजना होत् कृष्ण जलवाय क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी वे दी गई है।

2. पूनर्गिकत टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

अध्यक्ष

 डा. ए. के. मुखीपाध्याय, उप कुलपित कृषि विश्वविद्यालय, औरहाट, असम

जीन में जन्य मुखि विद्वविद्यालयी के उपकुलपीत

सदस्य

- 2. उप कालपति, बी. सी. के. थी., परिचम बंगाल ।
- उप क लगित, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इस्फाल, मणिपुर ।
- 4-48 (1) जीन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सिचन कृषि और उद्यान कृषि
 - (2) जीन में राज्य सरकारों के सचिव पक्षांसन
 - (3) जीन में राज्य सरकारों के सिचव, मछली पालन
 - (4) जीन में राज्य सरकारों के सिचव, सिचाई और कमान क्षेत्र
 - (5) जीन में राज्य सरकारों के वनीं के प्रधान चींफ/मुख्य संरक्षक

जीन में आने वाले राज्य

- (1) असम (दिसप्र)
- (2) पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)
- (3) अरूणाचल प्रदेश (इटा नगर)
- (4) मिणपूर (इम्फाल)
- (5) मेघालय (शिलांग)
- (6) मिजोरम (आईजनाल)
- (7) नागाल्ण्ड (क्रीहिमा)
- (8) त्रिपुरा (अगरतला)
- (9) सिकिकम (गंगरीक)
- 49. जीन में आने बाल राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिध
- 50. एन ए दी ए आर डी (नावार्ड) का सदस्य प्रतिनिध
- 51 क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी संगठतीं के अतिनिधि श्री नटबर मुक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, आक घर चचयनीलींग, जिला योकोकस्य, नागालैंग्ड
- 52. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिध
- 53. आई सी ए आर, मुस्यालय, नई दिल्ली का प्रीतिनिध
- 54. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि
- 55. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि
- 56. पर्यावरण और धन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि
- 57: बंजर भीम विकास विभाग, भारत सरकार का प्रीतिनिधि

- 58 निर्देशक, प्रयम्जा जायडु, हिमालय चिडियाघर वाजीलंग, (पश्चिम बंगाल) ।
- 59. जेनल आयोजना टीम के लिए संबस्य संविव को ए सी आर पी की कार्य कर रही विश्वितिशालय को गंबिधत दिभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अध्या कृष्य आधिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा अध्या कृष्य आधिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नहीं दिल्ली को सृष्यित ठरते हैं। कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वालं व्यक्ति की क्षमता उनके विषेक और उपलब्धता के आधार उनके विषेकानुसार नामित किया जाना है।
- आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:
 - (1) कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/ प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य गरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवाय जीनल आयोजना कार्य को सहायता की के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।
 - (2) पूर्व में प्राप्त किए गए कांकड़ों की जांच करना तथा उपक्षत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायिक ताथार पर कार्यात्मक योजना होत् अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिता सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में सबद करना
 - (3) मृदा, सतह तथा भीमणल जल, फसल लगाने को तरीको (क्रीचिंग पैट्रन) एक्ष्मिन एवं अत्य प्रासंगिटः श्रीयः तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनार्थ एवं इनके पर्यादरणीय, सामाजिक एवं आधिक कारकों को सम्बन्ध में कृषि-जलवाणिक क्षेत्रीय यंजना (एगीशार पी) आंकड़ों को विनिद्दिष्ट किया आयेगा ।
 - (4) क्षेत्रां एवं उपक्षेत्रों होता कमल उगाने के तरीके (क्रांटिंग पैटर्नस) निकासना एवं सुकाना ।
 - (5) गौर-फसल कवि, व्यक्तिकी, पश्यानन एवं शौत विशेष के लिये लपयक्त कवि प्रसंस्करण गीतिविधियाँ हो सम्बन्ध में सिफारियों करना ।
 - (6) क्षेत्र क्षे किष सम्बन्धी विकास होत माध्यीमक आहि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अविध (10 से 15 वर्ष) की जपस्कत स्कीमें/वार्यक्रमें को होगर करना तथा जनकी स्फिपिश करना; ऐसे पस्तार्थ को समय को चरणबद्ध अरना ।
 - (7) इसके जन्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का जनस-हारियन्त्र लेना और यदि अवश्यक हो सो जन्हें अधिकर कराना ।
 - (त) क्षेत्रकों को विकास होने विशेष कप में गोसे विकास को सहारना प्रकान करने में विजनीय संस्थाओं की भिष्का की जीव करना तथा आवश्यक नीनिनात ल्पाओं की सिफारिश करना,

- (9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये आसंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना,
- 4 दल की बैठक़ों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्तों के प्राथा भस्ते/मंहगाई अस्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/पंजालय/राज्य सरकार/विध्वविद्यालय द्वारा बहुन किया जायेगा तथा यो जना दल के गैर-सरकारी स्वस्थों के मामले में यह अपने थे जना आयोग द्वारा बहुन किया जायेगा।
- 5 योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना जायोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।
- 6. योजना दल अन्तिरिम रिपीट जैसे और जब आवश्यक हो, सींप सकता हो तथा वह अपनी अंतिम रिपीट कृषि-जलवायाणिक क्षेत्रीय योजना होस् रिपीटौं/जिला परिच्छोचिका एवं अन्य आंकड़ौं, की तैयारी की क्षेत्री के अनुसार सींपेगा।

आविश

आवेश विया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिश्विप योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागी एवं विभागों को संप्रीयत की जागे।

2 · यह भी आदश विया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जार्थ।

> एस. एन. कृष्टमचौधरी निवेशक (प्रकासन)

विनांक 14 जुलाई 1997

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी य्—भारत सरकार के चिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एगी का अतिकमण करते हुए पिचमी हिमालय क्षेत्र (जीन-1) से संबंधित योजना टीम को राजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता दोने के लिए पूनर्गठित किया जाता है। जित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौषी पंचवणीय योजना होत् कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दो दी गई है।

2 पुनर्गीठत टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

अध्यक्ष

 का आर. पी. प्रस्क त्यागी, उप क्लपित, हिमाचल प्रवेश कृष्णि विश्विष्यालय, पालमप्र, हिमाचल प्रवेश जीन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयां के उपकृतपति

सदस्य

- बा. बार्च, एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विक्वविद्यालय; (शाया उपचालाट), सीलन हिमाचल प्रवेश।
- 3 (1) कृषि विकान का शेरो कश्मीर विश्वविद्यालय, शालीमार कौम्स, श्रीनगर-191001 ।
 - (2) 45-बी, गांधी नगर, जम्मूतवी, जम्मू-18004 ।
- 4 पर्वतीय कृषि एवं वानिकी डीन कालेज, जीबीपीयएटी का रानी चौरी कैम्प्स (उप क्लपित के मनोनीस, जीबीपीयएटी पत नगर, (नैनीताल)

सदस्य

- 5-19 (1) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/ संचिद कृषि और उद्यान कृषि
 - (2) जीन में राज्य सकारों के सिचव, पशु पालन
 - (3) जीन में राज्य सरकार के समिव, मछली पालन
 - (4) जीन में राज्य सरकारों के स्थिय, सिंचाई और कमान क्षेत्र
 - (5) जोन में राज्य सरकारों के वनीं के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक ।

, जेत में आने वाले राज्य

- (1) जम्मू एवं कश्मीर
- (2) हिमाचल प्रदेश
- (3) उत्तर प्रदेश

सदस्य

- 20. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक का प्रीतिनिधि
- 21. एनं ए बी ए जार डी (नाबार्ड) का प्रतिनिधि
- 22. *क्षेत्र म^न संबंधित ग[#]र सरकारी-संगठनी का प्रतिनिधि
- 23. यंजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिध
- अहाँ सी ए आर, मस्यालय, नहाँ विल्ली का प्रतिनिधि
- 25. कृषि और सहकारिता विभागः, भारतः । सरकार का प्रतिनिधि
- 26 जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

- 27 पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिध
- 28. बंजर भूमि चिकास विभाग, भारत सरकार का प्रीतिनिध
- पशु पालन एवं. डियरी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

सवस्य-सचिव

30 . *जानल आयोजना टीम के लिए

"जानल झायोजना टीम के लिए सदस्य सिचव तथा गरें सरकारी संगठन के सदस्यों को ए सी जार पी के कार्य कर रहे विश्वयिद्यालय के सम्बन्धित विभाग से योजना टीम को अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आधिक-अनुसंधान कोन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई विल्ली को सूचित करते हुए क्षालतापूर्वक जंडपीटी कार्य करने शाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि में सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास होतु सिकय रूप से कार्य कर रहा हो।

- आयोजना टीम के विचारार्थ स्थिवय निम्नानुसार है :
 - (1) कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण प्रकासनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेआओं के अनुसार कृषि जलवाय जीनल आयोजना कार्य को सहायता दोने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हों निमलाना ।
 - (2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-अलबायियक आधार पर कार्यात्मक योजना होन् अपीक्षत किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्त्यन के निर्णय में मबब करना।
 - (3) मुदा सतह तथा भूभिगत जल फसल लगाने के सरीकें (क्रिंपिंग पेंट्रन) पश्चभन एवं अन्य प्रासंभिक क्षेत्रव तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनकें पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना (एसीजार पी) आंकड़ों को जिनिर्दिष्ट किया जायेगा ।
 - (4)' क्षेत्री एवं उपक्षेत्री होत फगल उगाने के सरीके (क्रिपिंग पैटर्नेस) निकालना एवं सुकाना '।
 - (5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पश्पालन एवं क्षेत्र निकेश के लिये उपयक्त किए एसंस्करण गतिनिधियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना।
 - (6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हुत् माध्यमिक अरू । (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अविध (10 को 15 वर्ष) की उपयुष्ट स्कीमी/कार्यक्रमें को लगा करना तथा उनकी सिकारिश करना; एसे गरताओं के समय की बरणबब्ध करना।

- (7) इसके उद्वरेगों के लिए आवश्यक श्रं सी उन्हें अधिकृत वारित्व लेना और यदि आवश्यक श्रं सी उन्हें अधिकृत कराना ।
- (8) अन्नकों के विकास में शिर्वाण रूप में , एरी जिकास को सहायता प्रदान करने में जिलीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना संथा आवश्यक नीरि गत उपायों की सिफारिश करना ।
- (9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रास्तिगत किसी अस्य पहलू पर विचार करना ।
- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सपस्यों के वात्रा भत्तं/महगाइ भत्तं का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/टिक्टिविद्यालय द्यारा वहन किका जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी स्वस्थों के मामले में यह क्रय योजना बायोग द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5. स्रोजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृष्णि), योजना आयोग को सम्बन्धित किया जा सकता है जो कृषि-जसकारिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्छ स्तरीय समिति के सदस्य-सिवद हैं।
- 6. शिषमा दल अल्लीरम रिपेट जैसे और जब आवश्यक हो, सीए सकता ही तथा वह अपनी अंतिम रिपेट किए-अलवायानिक अंतिय मैक्सा होत् रिपेटॉ/जिला परिच्छोदिका एवं अन्य आंकड़ों, की सीमारी की सार्वी के अनुसार सौंपेगा।

आवरा

जावेका दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिनिधि श्रीजन्म बल के अध्यक्ष एवं सदस्या; भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रीविह की जाये।

2. सह भी अस्तरेश विया जाता है कि सामान्य स्चनार्थ, संकल्प का अकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

> एस. एन. ब्रह्में चैंधरी. ृतिदोशक (प्रशासन)

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के विनांक 3 जून, 1988 को संकल्प सं. एम-13043/12/87-एनी का अतिक्रमण करमें हुए गंगा का विच्ला मैदानी क्षेत्र (जोन-3) हे संबंधित योजना टीम को योजना आधाग दिल्ली के कृषि जलकाम कोनीय मायोजना मनिट और अहमधाबाद में इसके यूनिट को महायता दोने के लिए प्राणित किया जाता है। विलीय क्षेत्रीय सायोजना मिनट कीर विच्छा योजना है । विलीय क्षेत्रीय सायोजना परियोजना को संजूरी वे दी गई है।

- 2. पूनर्गिठत टीम की संरचना निम्नानुसार होमी :---अध्यक्ष
 - का एम जी सोम, उप क्युबपित,
 विधानकन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी),
 मोहनपुर, जिला निविधा,
 परिचमी बंगाल

सनस्य

- 2--6 (1) कृषि उत्पादन आयुक्त/सिका, कृषि एवं उद्यान कृषि. परिषम बंगाल सरकार ।
 - (2) समिय, पशुपालन, पश्चिम बंगाल सरकार।
 - (3) स्विध, मछशी पालन, पश्चिम श्रीगाल सरकार।
 - (4) सचिव, सिचाई एवं कमान क्षेत्र, ,पश्चिम बंगाल सरकार ।
 - (5) पश्चिम बंगाल सरकार के बना के प्रधान चीफ/मृख्य संरक्षक । जोन में राज्य
 - (1) परिचय संगाल

सदस्य

- जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि ।
- एन ए टी ए आर डी (नाबाड़ाँ)
 का प्रतिनिधि।
- *क्षेत्र में संविधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि ।
- योजना आयोगः,
 भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- आर्ड सी ए आर, मृख्यालय, नर्ड दिल्ली का प्रतिनिधि ।
- कृषि और सहकारिला विभाग,
 भारत सरकार का प्रतिनिधि।
- प्रत संसाधन संत्रालय,
 भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- 14 पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि।
- 15 बंजर भूमि विकास विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- 16. पशु पालन एवं डयेरी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

17. *जोनस आयोजना टीम के लिए संवस्य-सचिव ।

"जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य समित एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रही विश्वविद्यालय को संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आधिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नर्द दिल्ली को सूचित करते हुए क्रुशलतापूर्वक अंडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विश्वेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर सरकारी संगठन एसा होना चाहिए जो जीन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास में सिक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

*गर-सरकारी संगठन के सदस्य को आयोजना टीम के अध्यक्ष स्वारी योजनी कायीग नहीं दिल्ली को सूचित करते हुए नामित कियों जाना है। यह गर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जीन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहा ही।

- 3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार ह⁵:---
- . (1) कृषि जलवान क्षेत्रीय आयेजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सदकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवान जोनल आयोजना कार्य को सहायता दोने के सिए संगत सूचना क आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिसीना।
- (2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपश्रेत्रीयकरण एक कृषि-जलवायिक आधार पर कार्यारमक योजना होत अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक स्वमा पर समायोजन/उन्नयन को निर्णय में मदद करना ।
- (3) मुवा, सतह तथा भूमिगस जल, फसल उगाने को तरीके (क्रोपिंग पेंट्रन) पश्चन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक सथा इन क्षेत्रकों को प्रोद्योगिकीय सम्भावनायों एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आधिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना (इसीबारपी) आंकड़ों को विनिविष्ट किया जायेगा।
- (4) क्षेत्री एवं उपक्षेत्रों होतू फसल उगाने के सरीके (फार्नोपिंग पैट्रनस) पिकालना एवं सूत्राना ।
- (5) गैर-फॅसस कृषि, बानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रस्त उरण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिकों करना ।
- (6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास होता माध्यमिक अयि (5 वर्ष) तथा साथ ही साम लम्बी वनिष (10 से 15

- वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों कार्यक्रमों को तर्योर करना तथा उनकी सिफारिक करना; एसे प्रस्तावीं की संविष् को चरणबद्ध करना ।
- (7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तर-दायित्व लेना और मदि आवश्यक हो तो उन्हें अधि-कृत कराना ।
- (8) क्षेत्रकों के विकास होतु विक्षेष रूप में, एसे विकास को सहायता प्रदान करने में विसीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक मीर्तिगत उपायों की सिकारिश करना ।
- (9) इसके कार्य एवं उद्विषयों के लिये प्रासंशिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।
- 4: दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के याचा भरतं/मंहगार्ड भरते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सबस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जाएगा तथा ग्रोजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के भागले में यह त्यय योजना आयीग व्वारा वहन किया जायेगा
- 5. योजना दब् के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सबस्य-संजिक हैं।
- 6. योजना चल अन्तरिम रिपोट जैसे और जब आवश्यक हाँ, सौंप सकता हाँ तथा वह अपनी अंतिम रिपोट कृषि-अलवायिक क्षेत्रीय योजना होतु रिपोटों जिला परिज्ञ दिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्गों के अनुसार सौंपेगा।

आदश

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिसिप योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों की संप्रेषित कीं भार्य।

2. यह भी आदशे दिया जाता है कि सामान्य स्वनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

> एसं. एनं बृह्मांचीधरीं निवधकं (प्रकासन)

संकल्प

नई दिल्ली. विनोक 14 जुलाई 1997

सं क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू-भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं एम-13943/12/87-एग्री का अतिकमण करते हुए मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र (जान-4) से सम्बन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमवाबाद में इसके यूनिट को सहायता दोने के लिये पुनर्गिटिस किया जाती है । विसीय

वर्ष (1997—2002) तक नौधीं पंचवर्षीय योजना होतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को संजूरी वे वी गई है प

2. पूनर्गठित टीम की गंरचना निम्नानुसार होगी :---

अध्यक्ष

 श. के. एस. चीहान, उप कुलपित, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, जिला समस्तीपुर, विहार-848125 ।

औन में 'अन्य कृषि विद्यविद्यालयों के उपकृतपति

सवस्य

- नरन्द्र द न , कृषि एवं प्रोच्छे रिक्त विषविद्यालय , कृपारगंज , जिला फ जाबाद , उत्तर प्रवेष-224001 ।
- 3-12 (1) जोन म⁻ राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुवत/सचित्र कृषि और उद्यान कृषि ।
 - (2) जोत भें राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन ।
 - (3) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन !
 - (4) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र ।
 - (5) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मृख्य संरक्षक ।

जीन में आने वाल राज्य

- (1) विहार
- (2) उत्तर प्रवेश
- 13. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी
 भूमि-विकास बैंक के प्रीतिधि ।
- 14 एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड) का
 सदस्य प्रसिनिधि।
- 15 क्षेत्र में सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
- योजना आयोग,
 भारत सरकार का प्रतिनिधि।
- 17 अाई सी ए आर, मुख्यालय, कई दिल्ली का प्रतिनिधि ।
- 18: कृषि और सहकारिता विभाग, -- भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- ी 19. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ()

- 20 पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- 21 बंबक्र भूमि पिकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि।
- 22. पशु पालन एवं डिय्री, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।।

सबस्य-सम्बद

23. *जीनल आयोजना टीम होतू सदस्य-सिमव ।

"ओनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सबस्य को ए मी जार पी के कार्य कर रही विद्यविद्यालय के संबंधित विभाग में योजना टीम के अध्यक्ष ब्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष ब्वारा योजना आयोग, नई विल्ली को सूचित करते हुए क्जलतापूर्वक जंडपीटी कार्य करने वाल व्यथित की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर सरकारी संगठन एसा होना चाहिए जो जोन में कृषि सथा मंगद्ध क्षेत्रों के विकास हेतू बिक्तय रूप से कार्य कर रहा हो।

- 3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानृसार हैं :--
 - (1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/ प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार औरजिला स्मर की अपेक्षाओं के अमुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता दोने के लिए संगत सूचना के आंकड़े एक करना और उन्हें मिलामा ।
 - (2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जललागिवक आधार पर कार्यारमक योजना होते अपेकिस किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर ममायोजन उन्नेशन के निर्णय में मवब करना ।
 - (3) मृता, सप्तह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रांपिंग पेंट्न) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक अंत्रक तथा इन अंत्रकों की प्रोद्योगिकीय सम्भावनायों एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आधिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों की विनिद्धिट किया जायेगा।
- (4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों होतु फसल उगाने के तरीके (क्रोंगिंग पैटर्नेस) निकालना एवं सुझाना 🏗
 - (5) गैर-फसल कृषि, धानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विद्योच के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिकारिकों करना ।

- (6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास होतु माध्यभिक मर्नाभ (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी मक्षि (10 स 15 थर्ष) की उपयुक्त स्कीमों कार्यक्रमों को तथार करना तथा उनकी सिफारिक करना; एसे प्रस्तावों के समय को परणवस्त्र करना ।
- (7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययमों का उतर-वायित्वः लेना और यदि अध्ययक हो तो उन्हें अधि-कृत इंडाना ।
- (8) क्षेत्रकों के विकास होते विशेष रूप मी, एसे विकास को सहायसा प्रदान करने मी वित्तीय संस्थाओं की मुश्रिका की जांच करना स्था आवश्यक नीतिनत उपांशों की मिकारिश करना।
- (9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।
- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सबस्यों के पाता भारतें में हुगाई भनते का अय, सरकारी सदस्यों के मामले में सबस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विध्वविद्यालय द्यारा बहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्यारा धहन किया जायेगा।
- 5. योजना वल को सम्बन्ध के कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जसवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उपन स्तरीय समिति के सबस्य-संचित्र हैं।
- 6. शंजना दल अन्तरिम रिपोर्ट और जैन आवश्यक हो, साँप सकता ही सथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायिकक भौगिय केजना होतु रिपोर्टी/जिला परिच्छोदिका एवं अन्य अकड़ों, की तैयारी की शर्ती के अनुसार सींपेगा।

आविध

शादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक-एक प्रतिकिपि गोजना दक के अध्यक्ष एवं सदरगों भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयी एवं विशाणों को संप्रीयत की भीगे।

2. यह भी आदोश दिया जाता है कि गामान्य सूलनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपण में कराया जाये।

> एस. एस. ब्रह्म्से**ची**धरी. सिंदोशक (श्रासन)

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी, यू-भारत अरकार के दिनांक 3 जून, 1998 के संकल्प में एम-13043/12/87-एकी का अतिक्रमण करते हुए उत्परी गंगा का मैदानी क्षेत्र (जान-2-421 GI/97

- (5) सं गंबंधित योजना टीम को योजना आयोग विल्ली के कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसमें यूनिट को एहागता वंने के लिए पुनर्गीठन किया जाता है, जिलीय वर्ष (1997-2002) तक भौबी पंचवदीय योजना होतु कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।
 - 2. पूनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :--

अध्यक्ष

श आई. पी. एस. यादव, उप कुलपित, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं द्रायीणिकी विश्वविद्यालय, कान्पुर, (उत्तर प्रदेश)-208002 ।

जोन भें अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकाुलपरित

सपस्य

- गौतिन्द बल्लब पंत कृषि एवं प्रीवीमिकी विश्वविद्यालय, (जीतीनीयूएटी), पंतनगर, जिला नैनीताल, उत्तर प्रवेश ।
- 3--7. (1) उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आधुक्त/सिषय, एवं उद्यात कृषि ।

आयुक्त/सिषध, कृषि एवं उद्यान

- (2) सिषय, पशुपालन, उत्तर प्रवेश सरकार।
- (3) समित, मछली पालन, उत्तर प्रदेश सरकार है
- (4) सचित्र, सिंभाई और कमान क्षेत्र, उत्तर प्रयोग गरकार ।
- (5) उत्तर पर्वाश गरकार के बनों के प्रधान चीफ/मृख्य संरक्षकः।

जोन में आने वाले राज्य

- (1) उत्तर प्रदेश ।
- 8. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी
 भृमि-विकास धैंक के प्रतिनिधि ।
- 9. एन ए जी ए आर डी (नाबाडी)का सवस्य प्रतिनिधि ।
- *क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रीतिनिधि।
- 11. योजना आयोगः भारत गरकार का प्रतिनिधि ।

- आई सी ए शार, मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
- कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि।
- 14. जल संसाधन मंत्रारुष,भारत सरकार का पतिनिधि ।
- 15. पगितरण और वस भेत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।
- बंजर भूमि विकास विभाग,
 भारत गरकार का प्रतिनिधि ।
- का पालन एवं डियरी,
 भारत करकार का प्रतिनिधि।

सदरय-सचिद

18. *अंतस आगोजना टीम होतू स्वस्थ-स्तिच्य ।

"फोसंट आर्यापना टीम के जिस सहस्य रुखिश धर्म ग्री सरकारी संग्राहरू को स सी आर भी ही हमा कर नहीं विश्वित द्यालय के संग्रीधन विभाग में शंकना टीम के अध्यक्ष बनाग अध्या कथि आर्थिक-अन्मेशार केन्द्र के रुध्यक्ष द्यारा गेवना आगोम, नहीं दिल्ली को रूपिन क्रमें झा काश्रुल्लागर्गक ग्रीपिनी कार्य करने वाले व्यक्ति की स्मास जनके विश्वेक और प्रश्लेक्सना के आधार उनके शिक्षेक्सनसार नामिन किया जाता ही । भीर सरकारी संगठन सोसा हाना चाहिता को जीन में किया एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास होत सक्तिय कर से कार्य कर रहा हो।

- आयोजना टीम के विधारार्थ विधेय निम्नानभार हैं:—
 - (1) क्रीय जलवाय क्षेत्रीय आशोजना के संस्थानीकरण/ प्रधारनीकरण के लिए गोजना आर्थण/राज्य सरकार क्षेत्र जिला क्ष्तर की अगोशाओं के अनसार कथि जलवाय जोतल आरोजना कार्य को सहायशा वासे के रिशा संगत स्वना क आंकड़ो एकक करना और उन्हें सिलाना।
 - (2) धर्म में प्रीप्त किया गया गरेशकों की जांच करनी तथा उपभोजीयकरण सर्व करिय-जलका विका आधार पर कार्यकाक योजना होता अमेशित किसी अन्य प्रासंस्थित स्वना पर समायोजन/उन्तरन की निर्णा में भदद करना।
 - (3) मदा, सरह तथा श्रीमगत जल, फसल लगावे के तरीके (क्रांपिंग फीट्र) दशकान, एवं अन्य प्रागंगिक क्षेत्रक तथा बन क्षेत्रकों की प्रीक्षेत्रकीय सम्भावनाय एवं इत्ये प्राटियनीय, सामाज्यिक एवं आधिक कारकों के सरबस्य में कृष्टि-जलकार दिक क्षेत्रीय बोजना (एक्शेआरमी) आंकड़ों की विकिस्टिट किया जोलेगा।
 - (4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हरेत फ़सल. उपाने के तरीके (कक्षेपिंग पैट्नुस) निकालमा एवं स्वास ।

- (5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पणुणलक एवं क्षेत्र विकोष के लिये उपयक्त कृषि प्रसंस्करण गीतिविधियों के सम्बन्ध की स्थितिकारिकों करना ।
- (6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास होतु माध्यम्थि अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लग्बी २ विध (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमी कार्यक्षमी को तैयार करना तथा उनकी सिफारिक करना; एसे प्रस्तावों के समय को वरणबंद्ध करना।
- (7) इसके उद्देश्य के लिए आध्ययक अध्ययनों का उत्तर-दायिक लेना और यदि आवस्यक हो हो उन्ह³ अधि-कृत कराना ।
- (8) क्षेत्रकों के दिकार होता विशोध रूप से, एसे विकास को सहयान प्रवान करने में विसीय संस्थाओं की भूमिका की जांच रूसना तथा आवश्यक मीसियत उपाणी की सिफारिक करना ।
- (9) इसके कार्य एवं जब्बेक्यों के लिये प्रारंगिक किसी अन्य पहला पर विचार करना ।
- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भारिताई भरते का व्यय, सरकारी स्वस्यों के मामले में सतस्य के अध्ये विभाग/गंत्रालव/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय व्यारा बहुन किया आएगा तथा गोजना दल के गेर-गरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5. योजना इत के सम्बन्ध में कोर्ड भी पत्राचार असाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधिक किया जा सकता है जो कृषि-जनशायिक क्षेत्रीय रीजना परियोजना पर उच्च रवरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।
- 6. योजना सल अस्तिरम रिपोर्ट ग्रीमे और जब आवश्यक हो, सींप सकता है सथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट किप-जनमायिक क्षेत्रीय गोजना होत् रिपोर्टी/जिला परिकारिका एवं अन्य आंकहों स्त्री तैयारी की कर्ती के सत्सार सींपेगा।

आब ्र

आदेश विया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिण योजना वल को अध्यक्ष एवं स्वत्यों, भारत संरक्षार एवं राज्य सरकारों को सभी संबंधित मंधालयाँ एवं विभागों को संप्रेषित की पार्य।

2. यहभी आदेश दिया जाता है कि सामान्य स्पनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपूत्र में क्राया जारे।

> एस. एन. बृह्सोन्नीभरी निद्यास (प्रशासन)

संबस्य

सदस्य

सवस्य

संकरूप

भारत सरकार के विनांक 3 जून 1988 के संकर्ष संव एम-13043/12/87-एग्रो का अतिक्रमण करते हुए गंगा पार के मैदानी क्षेत्र (जीन VI) संबंधित योजना टीम को योजना आयोग विश्ली के इधि जलवायु क्षेत्रीय आयोजन यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है, विस्तीय वर्ष 1997-2002) तक नौंत्री पंचवर्षीय योजना हेतु इधि जलनायु सेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी वे दी गई है।

- 2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी:
- 1. डा॰ अमरजीत सिंह खैरा, उप कुलपति अध्यक्ष पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

जोन में अन्य कृषि बिश्वविद्यालयों के उपकुलपति

- 2. चौ० चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा-125004
- राजंस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकाने र-334000 सबस्य
- 4-28 (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव कृषि और उद्यान कृषि असस्य
 - (ii) जोत में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन सदस्य
 - (iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन सदस्य
 - (iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र
 - (v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ मुख्य सरक्षक सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

- (i) पंजाब
- (ii) हरियाणा
- (iii) राजस्वान
- (iv) चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र
- (v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विल्ली
- 29. जोन में आने वाले राज्यों की सहकारी भूमि सदस्य
- 30. एन ए बी ए आर डी नावार्ड का सदस्य प्रतिनिधि सदस्य
- 31. क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य
- 32. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिध

सद्द्रस

- 33. आई सी ए आर मुख्यालय, नई विल्लो का प्रतिनिधि
- 34. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि सबस्य
- 35. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
- 36. पर्यावरण और श्रम मंझालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि सवस्य
- 37. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
- 38. पणुपालन हेयगे भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

सदस्य सन्धिध

39. जोनल आयोजना टीम हेतु सबस्य सचिव जोनल आयोजना टीम के लिए सवस्य सचिव गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विद्यालय के सर्वाधित विभाग से योजना टाम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई विल्ला को स्चित करते हुए कुं जलता पूर्वक जेडपाटा कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार, उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है, गैर सरकारा संगठन ऐसा छोना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सब्ध क्षेत्रा के विकास में सिक्तय रूप से कार्य कर रहा हो।

- आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:
 - (i) कृषि जलवायु क्षेत्राय आयोजना के सांस्थानाकरण प्रचालनाकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिलास्तर की अपकाओ के अनुसार कृषि जलवायु जोनक आयोजना कार्य को सहा-यता देने के लिए संगत सूचना आंकड़े एकत करना और उन्हें मिलाना।
 - (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ की आंध करना तथा उप क्षेत्रीयकरण एवं कृषि व जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु आपेंकित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उम्नयन के निर्णय में मदद करना ।
- (iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के
 तरीके, (क्रोपिंग पैटर्न) पश्चमन, एवं अन्य
 प्रारांगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय
 राम्भावनाओं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं
 आधिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जसकाविक
 क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को
 विनिविष्ट किया जायेगा।

- (iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फ त उगाने के तरीके
 (क्रोंपिंग पैटर्न) निकालना एवं सुझाना,
- (v) गर फसल कृषि वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिणें करना,
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी बिकास हेतु माध्यमिक अवधि (5वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 रो 15 वर्ष) की उपनुक्त स्कीमों/ कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को बचनबद्धता करना
- (vii) इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्राधिकृत करना,
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रवान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना,
- (ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलु पर विचार करना।
- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में टीम के सदस्यों के याजा भरते / बहुंगाई भरते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंज्ञालय/राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा बहुन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर / सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्नाचार सलाह-कार (कृषि योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक कोलीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव है।
- 6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी आन्तिम रिपोर्ट कृषि जलवायाविक केन्नीय योजना हेतु रिपोर्टी/जिला परिच्छेदिका एक अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सींपेगा।

आदेश .

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-तिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंत्रालयों एवं विभागों को संबोधित की जाये।

 यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत में कराया जाये।

> एग० एन० **बह्योची**धरी निदेशक (एशासन)

संक्र≂प

सं० क्यू०-11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०-भारत सरकार ने विनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम13043/12/87-एमी का अतिक्रमण करते हुए पूर्वी पठार
एवं पर्यंतीय क्षेत्र (जीत-VII) से संबंधित योजना टीम को
मीजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना
यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के
लिये पुनर्गठित किया जाता है। विसीय वर्ष (1997--2002)
तक नौंबी पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय
आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

 डा॰ के॰ प्रधान, उप कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नुवनेश्वर पिन-751003 मध्यक्ष

जोन में अन्य कृषि विष्वविद्यालयों के उपकुलपति

 विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर जिला नादीया, पश्चिम

गाल

सदस्य

 इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रवेश)

सदस्य

 बिरसा कृष्टि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, बिहार, पिन कोड-834004

 पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकीला, , महाराष्ट्र .

संबस्य

30. (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सिचव कृषि और उद्यान कृषि

सदस्य

(ii) जोन में राज्य सरकारों के समिव पणुपालन

सदस्य

(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन

सबस्य

(iv) जोन में राज्य संरकारों के सचिव. सिंचाई और कमान क्षेत्र

सदस्य

(v) जोन में राज्य सरकारों के बनों के प्रधान चीफ प्रधान/मुख्य संरक्षक

सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

- (i) उड़ीसा
- (il) पश्चिम 'गाल
- (iii) मध्य प्रदेश
- (iv) विहार
- (५) अहारास्ट्र

	·
31. जोत में काते वाले राज्यों के सहकारी मूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
32. एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	• सदस्य
33.* क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी. संगठमों के प्रतिनिधि	सदस्य
34. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
35. आई ० सी० ए० आर० मुख्यालय, नर्डे दिल्लीका प्रतिनिधि	सवस्य
36. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
37. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
38. पर्यावरण और वन मोत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
 बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि 	सदस्य
40. निदेशक पदमजा नायडू, हिमालय चिडिया घर दार्जीसंग (पिण्वम बंगाल)	सदस्य

41. डा॰ बी॰ भूयन, प्रोफेसर तथा कृषि अर्थगास्त्र के प्रमुख, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी निष्नविद्यालय, भृवनेष्वर-751003।

*गैर-सरकारी संगठनों को आयोजना टीम के अध्यक्ष दिरासोजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एर्व सम्बन्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यकर रहा हो।

- आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
- (i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण प्रचालनीकरण के लिये योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनस आयोजना कार्य को सहायता देने के स्रिये संगत सुचना व आंकड़े एकल करना और उन्हें मिलाना।
- (ii) पूर्व में प्राप्त किये गये शांकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेतीयकरण एवं कृषि जलवायिक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।
- (iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (कोपिंग पेंद्रत) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक विकास स्थाप इस क्षेत्रकों की प्रीद्योगिकीय संभाषनाई

एवं इनके पंयोवरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जसवायिक कोदीय योजना (ए० सी० आर० पी०) आंकड़ों को विनिविष्ट किया जायेगा।

- (iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस्) निकालना एवं सुझाना।
- (v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिबिधियों के सम्बन्ध में सिफारियों करमा।
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हे जु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपमुक्त स्कीमों/ कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिकारिश करना, ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।
- (vii) इसके उद्देश्य के लिये आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आधश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में विक्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।
- (ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।
- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के मामले माला भते/महंगाई भने का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा गहन किया जायेगा तथा योजना वल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा गठन किया जायेगा।
- 5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पक्षाचार सलाह-कार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य मित्रव हैं।
- 6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सींप सकता है तथा वह अपनी अन्तिम जिला रिपोर्ट कृषि जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टी जिला परिच्छेदिका एव अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्ती के अनुसार सांपेगा।

आदेश -

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-लिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंत्रालयों एवं विभागों की संप्रेषित की जागे।

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सवस्य

सधस्य

सदस्य

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राज्यन में कराया जाये।

> एस० एन० ब्रह्मोचौधरी, निदेणक (प्रणासन),

संकरूप

सं० करू० 11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०--भारा सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प तं० एन०-13043/12/87-ए ग्री का अतिक्रमण करते तुए केन्द्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन-VIII), से संबन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु केन्नीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को महायता देने के लिये पुनर्गठित किया जाता है, बिलीय वर्ष (1997-2092) एक नौतीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को गंजूरी दे दी गई है।

- 2. पूनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।
- डा॰ पंजाब सिंह, उप-शुलपनि अध्यक्ष जयाहर साल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
 (जे॰ एन॰ के॰ वी॰ वी॰) मध्य प्रदेश-जलपुर482004)

जोन में अन्य कृषि विग्यविद्यालयों के उप-कुलपति

- 2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर- सदस्य 334001
- चन्द्रमेखर आजाद कृषि एवं भौचोगिकी विग्व∽ विश्वालय, कानपुर-208002 सदस्य
- 4-18 (i) जान में राज्य सरकरों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचित्र कृषि और उद्यान कृषि सदस्य
 - (ii) जीन में राज्य सरकारों के सचिव, पशुपालन सबस्य
 - (iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव. मध्यी पालन सदस्य
 - (iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव. .
 सिवाई और कमान क्षेत्र सदस्य
 - (v) जीन में राज्य सरकारों के बनों के प्रधान चीफ/मृख्य सरक्षक सदस्य

जोनं में आने वाले राज्य :

- (i) मध्य प्रदेश
- (ii) उत्तरप्रदेश
- (iii) राज्य**ण**ान

19.	जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी	भूमि	
	विकास बैंक के जितिनिधि	••	

20. एन ॰ ए० वी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) ं का सबस्य प्रतिनिधि

21. *अंत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि

22. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

23. आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

24. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

25 जित्र संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

26. पर्याजरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

27 वंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

28. पशु पालन एवं डियरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य सचिव

सदस्य

29. *जीनल आयोजना टीम हेत् सदस्य

*जोनल आयोजना टीम के लिए सबस्य सिंचव एवं निर-सरकारी संगठन के सबस्य को एसी आर पि के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष हारा अयवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष हारा योजना आयोग, नई बिहली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की अमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेत कार्य कर रहा हो।

- आयोजना टोम के निचारार्थ विषय निम्नानुसार है :---
 - (i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानी-करण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/ राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना य आंकड़े एकत करना और उन्हें मिलाना।
 - (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि जलवायिक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेकित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयम के निर्णय में मक्द करना।

- (iii) मृदा, सतह था भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोदिंग पैटर्न) पशुक्षन, एवं अत्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिक क्षेत्र सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावन्यीय, सामाजिक एवं जाधिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जलवायविक, क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- (iv) क्षेत्री एवं उपक्षेत्री हेतु फमल उगाने के तरीके
 (क्षोपिंग पैटर्न) निकालना एवं सुझाना ।
- (v) गैर-फसल कुषि, वानिकी, पणुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गति-यिधियों के सम्बन्ध में सिकारिशें करना।
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यसिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/ कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तायों के समय को जरणबद्ध करना।
- (vii) १ सके उरेश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदाधित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।
- (viii) क्षेत्रकों के चिकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की कौच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की मिकारिश करना।
 - (iz.) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक शिक्षी अन्य पहल पर विचार करना ।
- 4. सल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सबस्यों के बाला भले/महंगाई भले का व्यय, सहकारी सदस्यों के मामले में सबस्य के अपने विभाग/मल्लालय राज्य सरकार/विश्य-विद्यालय द्वारा बहुन किया जायेगा सथा योजना दल के गैर/सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग दारा बहुन किया जायेगा।
- 5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाह-कार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित कियाजा सकता है जो कृषि जलवाधिक क्षेत्रीय योजना परियोज । पर उल्च स्तरीय समिनि के सदस्य-सन्तिव हैं।
- 6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सींप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट धृपि जलवाथाविक क्षेतीय योजना हेतु रिपोर्टी/जिला परिच्छेविका एवं अन्य आकड़ों को नैगरी को शर्जी के अनुवार पींगेगा।

अधिश

आदेश विया जाता है जि इसे. संकर्ण की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार, एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंतालयों एवं विभागों को संग्रेषित की जाये।

2. यह भी आवेण दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकल्प का प्रकाणन, भारत के राजपन में कराया जाये।

> एस० एम० ब्रह्मांचीधरी निदेशक (प्रणासन)

संकरप

सं वयू०-11012/2/97-98-ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के विनांक 3 जून 1988 के संकरण सं० एम— 13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पिष्णिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र (जीन IX) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिस्ली के कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना म्निट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। बित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना गरियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

- 2. पुनर्गेठित टीम की संरचना निम्नानुसार होती:
- डा० वाई० एस० नेरकर, उप-कुलपित, अध्यक्ष सहात्मा फृत्रे कृषि विद्यापीठ, (एम पी केवी), राव्री, जिला अहमद्यनगर, महाराष्ट्र-413722

जोन में अन्य कुषि विश्वविद्यालयों के उप-भुलपति

- २. पंजाबराव देशमुख, कृषि विद्यापीठ . सदस्य (पीकेवी), कृषि नगर, अकोला, महाराष्ट्र-444104
- 3. जबाहर लाल नेहरू कृति विश्वविद्यालय संधस्य (जेएन के बी)-482004 जबलपुर, (मध्य प्रदेश)
- राजस्थान कृषि विष्वविद्यालय, बीक्रानेर-33400 सदस्य
- 5-19. (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन सदस्थ आयुक्त/सचिष कृषि और उद्यान ृषि
 - (ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सदस्य प्रणुपालन
 - (i i) जोन में राज्य सरकारों के सनिव, सदस्य मछली पालन
 - (iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, शवस्य सिंवाई श्रीर कमान क्षेत्र ।

(v) जोन में राज्य सरकारों के वर्ती के सदस्य प्रधान की के मुख्य सरक्षक 133 114 1 1 1 1 1

जीन में प्राने वाले राज्य

- (i) महाराप्ट्र
- (ii) मध्य प्रदेश
- (iii) राजस्थान
- 20. जोन में भ्राने वाले राज्यों के मङ्कारी सदस्य भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि।
- 21. एन० ए० बी० ए० श्रार० डी० (नाबार्ड) का सदस्य सबस्य प्रतिनिधि।
- 22. *क्षेत्र से संबंधित गैर सरकारी संगठनों सवस्य के प्रतिनिधि ।
- 23. योजना श्रायोग, भारत सरकार का ् सदस्य प्रसिनिधि ।
- 24. श्राई० सी० ए० श्राप्त मुख्यालय, नई सवस्य विस्ली का प्रतिनिधि ।
- 25. कृषि भौर सहकारिता विभाग, भारत सदस्य सरकार का प्रतिनिधि ।
- 26. जत संमाधन मंत्रालय, भारत सर्कार सदस्य का प्रतिनिधि !
- 27. पर्यावरण श्रीर वन म'वालय, भारत सवस्य मरकार का प्रतिनिधि । .
- 28. वंजर भूमि विकास विभाग, भारतं सदस्य सरकार का प्रतिनिधि ।
- 29. पशु पालन एवं डेयरी, भारत मरकार सवस्य का प्रतिनिधि ।
- 30. *जोनल प्रायोजन टीम हेतु सदस्य~ संवस्य मंचिय । सिवर

*जोनल ग्रायोजना टीम के लिए सबस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सबस्य को ए० सी० ग्रार० पी० के कार्य कर रह विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के प्रध्यक्ष द्वारा श्रयमा कृषि ग्राधिक श्रनुसंधान केन्द्र के श्रध्यक्ष द्वारा योजना श्रायोग, नई विल्ली को सुचित करते हुए कुशल-नापूर्वक जेइपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक श्रीर उन्तव्धता के ग्राधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाता है। गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के विकास होनू सिक्षय रूप से कार्य कर रहा हो।

- 3. ब्रायोजना टीम के विचारायं विषय निस्तानुसार है:
 - (i) इति जलवायु क्षेत्रीय ग्रायोजना फें सांस्थानीकरण/ प्रवालनोकरण के लिए योजना ग्रायोग/राज्य सरकार

श्रीर जिला स्तर की श्रपेक्षाश्रों के श्रनुसार कृषि जलवाय जोनल शायोजन कार्य को सहायता देने के लिए सगत सूचना व पांकड़े एकत करना श्रीर उन्हें मिलाना।

- (1i) पूर्व में प्राप्त किए गए श्रांकड़ों की जांच करता तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि⊸जलवायिकि श्राधार पर कार्यात्मक योजना हेतु श्रपेक्षित किसी श्रन्य प्रात्तिक सूचना पर समायोजन उन्नयन के निर्णय में मदद करना।
- (iii) मृद्या, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के
 तरीके (क्रोपिंग पेंट्रन) पगुधन, एवं अन्य प्रास्तिक
 क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रोद्योगिकीय संग्रदारें
 एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रार्थिक कारकों
 के सम्बन्ध में कृषि जलवायिक क्षेत्रीय योजना
 (ए०सी०आर०पी०) अकिडों को विनिर्दिष्ट किया
 जायेगा।
- (iv) क्षेत्रों एवं उपजेत्रों हेत फसल उगाने के तरीके (क्षेपिंग पैटर्नस) निकालना एवं स्क्षाना ।
- (v) मैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना।
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेत् माध्यमिक ग्रवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी प्रयधि (10 रो 15 वर्ष) की उपस्कत स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।
- (vii) इसके उद्देश्य के लिये भ्रावश्यक श्रद्धयनों का उत्तरदायित्व लेना श्रीर यदि श्रावश्यक हो तो उन्हें श्रिष्ठकृत कराना ।
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हैत् विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रवान करने≈में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा श्रावश्यक नीतिगत : उपायों की सिफारिश करना।
 - (ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार नार्ना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भतें।महगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के प्रवने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा बहुन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना प्रामोग द्वारा वहन किया जायेगा।

 योत्रना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावार सलाह-कार (कृषि), योत्रना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता

सर्वस्य

है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

 योजना जल प्रन्तरिम रिपोट जैसे ग्रौर जब आवश्यक हो, सींप सकता है तथा वह भ्रपनी श्रांतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेत् रिपोटों/जिला परिचछेविका । एवं प्रन्य आंकड़ों, की तैयारी की शती के अनुसार सौंपेगा ।

श्चादेण

आदेश विथा जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-लिपि योजना दल के प्रध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को संप्रेधित की जाये।

2. यह भी श्रादेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकरप का प्रकाशन, भारत के राजपन्न में कराया जाये

> एस० एन० उहाीचीधरी निदेशक (प्रशासन)

सं करूप

सं०-क्यू-11012/2/97-98 ए० आर**० पी० यू०--भार**त सरकार के दिलांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम०-13043 12/87-एग्री का अंतिकमण करते हुए दक्षिणी पठार एवं पवर्तक्रिय क्षेत्र (जोन-10) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग विल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना युनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गटित किया जाता है। बिसीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायुः क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजरी दे दी गई है।

- 2. पूनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।
- 1. ञा० पी० महावेश्वपा, उन कुलवित, अध्यक्ष कृषि विज्ञान विषवविद्यालय, धारवाड् (कर्नाटक)

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकृतपति

2. आम्ध्र प्रवेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-5,00030.

सदस्भ

3. तमिलनाड् कृषि विश्वविधासय कोयम्बटुर-641003.

सदस्य

 फुषि विज्ञान विषवनिधालय बंगलीर, कर्नाटक-560065

सदस्य ्र

(i) जोन में राज्य सरकारों के इः वि सदस्य उत्पादन आयुक्त/सचित्र कृषि और उत्तान कृषि

3-421 GI/97

(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव

(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचित्र, सबस्य मछली पालन

(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सदस्य मिचाई और कमान क्षेत्र

(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों सदस्य के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक

जोन में आने वाले राज्य

- (i) आन्ध्र प्रवेश
- (ii) कर्नाटक
- (iii) सभिलनाड्

20. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-सदस्य विकास बैंक के प्रतिनिधि

21. एन०ए०बी०ए०आर०छी० (नाबार्ड) संबस्य का सदस्य प्रतिनिधि

22. *क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि

23. योजना, आयोग भारत सरकार का प्रतिनिधि

24. अाई०सी०ए०आर, मुख्यालय सदस्य नई दिल्लीका प्रतिनिधि

25. कृषि और सहकारिता विभाग, सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि

26. जल संसाधन मंद्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

27. पर्यावरण और वन मंत्रालय, सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि

28. इंजर नृपि थिकास विभाग, भारत मरकार का प्रतिनिधि

29. पणु पालन एवं डेयरी भारत सरकार का प्रतिनिधि

30. "जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य समिव सदरय-समिव

^कजोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गेर सरकारी संगठन के सदस्य की ए० सी० आरं० पी० के कार्य कर रहे विश्व-विद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आधिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नहें दिल्ली को सूचित करते हुए मुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर सरकारी

सदस्य

सदस्य

स कर्म

सदस्य

सदस्य

संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबंद क्षेत्रों के विकास हेतु सिकय रूप् से कार्य कर रहा हो ।

- आयोजनाटीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
- (i) इति जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/ प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकल करना और उन्हें मिलाना।
- (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्तयन के निर्णय में मदद करना ।
- (iii) मृदा, सवह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (कीपिंग पेंट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक केंद्रका तथा इन क्षेत्रकों की प्रोधोगिकीय सम्भावनायों एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सबन्ध में कृषि—जलवायिक क्षेत्री र राजना (ए०मी० जार जपेंग) आकड़ों को विनिद्धिंट किया जायेंगा।
- (iv) क्षेत्रों एव उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग ,पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।
- (v) गै?-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारियों करना ।
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक श्रविध्व (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी श्रविध्व (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रम्तावों के सनय को चरणवद्ध करना।
- (vii) इसके उद्देश्य के लिए, श्रावश्यक अध्ययनो का उत्तर-वायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशोष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिकारिण करना।
- (ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी भ्रन्य पहल् पर विचार करना।
- 4. दल की वैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के याला मत्ते/महगाई भर्ते का व्यय, सरकारी सबस्यों के मामने में सबस्य के अपने विभाग/म ज्ञालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा धहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना श्रायोग द्वारा वहन किया जायेगा।
- योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्नाचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो

कृषि - जलवायिक क्षेत्रीय योजना परिग्रोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव है ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपॉट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट फुषि-जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपॉटों/जिला परिच्छेविका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

श्रादेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के श्रध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बंधित महालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये।

 यह भी आदेश दिया जाता है कि झामान्य सुचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाय।

> एस० एन० बहुगेषीधरी निषणक (प्रशासन)

संकरूप

सै० क्यू०-11012/2/97-98 ए० श्रार० पी० यू०भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एक०13043/12/87-एग्री० का श्रतिक्रमण करते हुए पूर्व तटीय
मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र (जीन -XI) से सम्बन्धित यीजना
टीम को योजना श्रायोग दिल्ली के क्षृषि जलवायु केत्रीय
प्रायोजना यूनिट और श्रहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता
देने के लिए पूनगंठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (19972002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्षुषि जलवायु
क्षेत्रीय श्रायोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

1. डा॰ ए॰ अन्दुल करीम, उप कुलपति, अध्यक्ष तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बट्र 641003।

जौन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

- प्रांध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030
- उड़ीमा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर—751003

4-23(i) जोन में राज्य सरफारों के कृषि उत्पादन ग्रायुक्त/सचित्र कृषि और उद्यान कृषि

- (ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन
- (iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन

सदस्य

सदस्य सदस्य

सदस्य

स्रदस्य

	रत का राजान, ज
(iv) जोन में राज्य सरकारों के सि सिचाई और क्रमान क्षेत्र	चेव, सदस्य
(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक	` सदस्य
जौन में म्राने वाले राज्य	
(1) म्राध्न प्रदेश	
(2) उड़ीसा	
(3) तमिसनाडु	
(4) पांडिचेरी सं व क्षेत्र	,
24. जोन में ग्राने वाले राज्यों के सहका भूमि- विकास बैंक के प्रतिनिधि	री सदस्य
25. एन० ए० बी० ए० घार० डी० (न का सबस्य प्रतिनिधि	ा बार्ड) सदस्य
26. *क्षेत्र, में सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सद स्थ
27 योजना भायोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
28. श्रोई० सी० ए० श्रार०, मुख्यालय, नई विल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
29. ऋषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
30. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	म द स्य
31. पर्यावरण और वन मतालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	. सदस्य
32. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
33. पशुपालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि	, सवस्य
34. *जोनल ब्रायोजना टीम हेतु सदस्य	सदस्य-सर्विव

*जोनल ग्रायोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० ग्रार० पी० के काय कर रहे विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग से योजना-टीम के प्रध्यक्ष द्वारा ग्रथवा कृषि प्राधिक-श्रनुसंधान केंद्र के प्रध्यक्ष द्वारा योजना ग्रायोग, नई दिस्ती को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के श्राधार पर उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेसु सिक्य रूप से कार्य कर रहा हो।

सचिव

- 3. श्रायोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :
- (i) क्वर्षि जलवायु क्षेत्रीय ग्रायोजना के सांस्थानीकरण/ प्राचालनीकरण के लिए योजना ग्रायोग/गज्य संरकार और

जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवाय जोनल आयोजना कार्य की सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत करना और उन्हें मिलाना।

- (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आक्षकों की जांच करना तथा उपभोत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायिक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्यः प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मबद अरना ।
- (iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (कोषिंग पेट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायों एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि—जलवायविंक क्षेत्रीय योजना (ए० सी० आर० पी०) आकड़ों को विनिर्दिट किया जाएगा।
- (iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेलु फसल उगाने के तरीके (कोपिंग पैटर्नेस) निकालना एवं सुझाना ।
- (v) गैर--फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।
- (vi) क्षोत्र के कृषि मम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10म 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना, ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।
- (vii) इमके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययना का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें आधिकृत कराना ।
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को महायता प्रदान करने में विताय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।
- (xi) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलु पर विचार करना ।
- 4. वल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के महस्यों के याता भत्ते/मंहगाई भन्ने का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामने में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना वल के गैर--सरकारी सदस्यों के मामने में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।
- 5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना प्रायोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि—जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर अच्च स्तरीय ममिति के सदस्य—सचिव हैं।

6. योजना इस अन्तरिम रिपोटों जैसे और जब कावश्यक हो, सींप सकता है तथा वह कानी प्रान्तम रिपोर्ट कृषि— जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोटों/जिला परिच्छेदिका एतं अन्य श्रांकडों, की तैयारी की गतों के अनुसार सींपेगा।

श्रादेश

श्रादेश दियां जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के श्रध्यक एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेपित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि तोमान्य सूचनार्थ, संकरण का प्रकाशन, भारत के राज्यत में कराया जाए।

> एस० एम० ब्रह्मोचीधरी, निदेणक (प्रणासन)

संक्ष्प

सं० क्यू०-11012/2/97-98 ए० आए० पी० यू०-भारत सरकार के विनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं०
एम-13043/12/87-एमी का ग्रात्तिभण करत हुए पिक्लम
तटीय मैदान एवं बाट क्षेत्र (जोन--12) से संबंधित योजना
टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय
आयोजना यूनिट श्रीर अहमदीबाद में इसके यूनिट को सहायता
वेने के लिए पुनर्गटित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नींनीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु
क्षेत्रीय श्रायोजना परियोजना को मंजूरी दे ही गई है।

- 2. पुनर्गेठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।
- डॉ० ए० जी० सायन्स, उप कुलपति अध्यक्ष कॉंकज कृषि विद्यायी, दपोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र--415712 ।

जोन में श्रम्य कृष्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

- 2. फेरल कृषि विश्वविद्यालय, बेह्लनीविकरा, सदस्य विज्र--680654 ।
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, झारवाइ, सबस्य कर्नाटक ।
- 4. तमिलनाडु कृषि विश्वविधालय, सबस्य कोयम्बद्रर---641003 ।
 - (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि सदस्य उत्पादन भ्रायुक्त/राश्विय कृषि और उद्यान कृषि ।
 - (ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव सदस्य पशुपालन ।

- (iii) जोन में राज्य सरकारों के सिवत, सबस्य मछली पालन ।
- (iv) जोत में राज्य 'सरकारों के सजिव, सदस्य सिवाई ग्रीर कमान क्षेत्र ।
- (∀) जोत में राज्य सरकारों के बनों के सवस्य प्रजात चीक मुख्य∤गंरक्षक ।

जोन में माने वाले राज्य

- (i) केरल
- (ii) तमिलनाड्
- (iii) कर्नाटक
- (¡V) महाराष्ट्र
- (v) गोवा
- (vi) पांडिनेरी (माहे)

35 जो। में बाने वाने राज्यों के सहकारी **सवस्य** भूषि--विकास बंक के प्रतिनिधि ।

36. एन० ए० बो॰ ए० श्राद० औ॰ (नाक्षार्ड) सवस्य का सथस्य प्रतिनिधि ।

37. *अंत्र में संबंधित गैर-सरकारी- सवस्य संगठनों के प्रतिनिधि ।

38. योजना आयोग, भारत सरकार का सरस्य प्रतिनिधि ।

39. भाई० सी० ए० भार०, मुख्यालय, सबस्य नई दिल्ली का प्रतिनिधि

40. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सदस्य सरकार का प्रतिनिधि ।

41. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य का प्रतिनिधि ।

42. पर्थावरण श्रीर वन मंत्रालय, भारत सबस्य सरकार का प्रतिनिधि।

43. जजर भूमि विकास विभाग, भारत सदस्य सरकार का प्रतिनिधि ।

44. पशु भौतन एवं डेयरी, भारत सरकार सदस्य का प्रतिनिधि।

45. **जोनल श्रायोजना हेतु सपस्य सचिव जोनल श्रायोजना टीम के लिए सदस्य मचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० श्रार० पी० के कार्य कर रहे विशव-विद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के सध्यक्ष द्वारा मथवा कृषि आधिक-श्रनुसंधान केन्द्र के श्रध्यक्ष द्वारा योजना श्रायोग, नई दिल्ली को सुचित करते हुए कुणनवापुर्वक जड़०

पी व्टी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विदेक ग्रीर उपलब्धता के श्राधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेत् सिक्तय रूप से कार्य कर रहा हो।

- अप्रापोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार
 - (i) कृषि जलवाय श्रेतीय सायोजना के सांस्यानीकरण प्रचालनीकरण के लिए योजना सायोग/राज्य सरकार स्रीर जिला स्तर की स्रपेक्षामों के सनुसार कृषि जलवाय जोनल सायोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना त्र स्रोकड़े एकत करना श्रीर उन्हें मिलाना ।
 - (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की आंच करना तथा उपसंजीयकरण एव कृषि-जलवायिक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्तयन के निर्णय में मदद करना।
 - (iii) मुद्दा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के
 तरीके (ऋषिण पेंड्रेन) पणुधन, एवं अन्य
 प्रास्तिक क्षेत्रक तथा इत क्षेत्रकों की प्रोद्योगिकीय
 सम्भावनाय एवं इनके पर्यावणीय, सामाजिक एवं
 ग्राधिक फारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायिक
 क्षेत्रीय योजना (ए०सी०ग्रार०पी०) श्रांकड़ों को
 विनिविष्ट किया जाएगा।
 - (¡v) क्षेत्रां एवं उपक्षेत्रों हेत् फसल उगाने के तरीके (क्षोपिंग पैटनर्स) निकालना एवं सुद्धाना ।
 - (v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिय उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध से सिफारिशें करना ।
 - (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अविद्धि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अविद्धि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीभो/कार्यकर्मों को तियार करना तथा उनकी सिकारिश करना, ऐसे प्रस्तानों के समय को चरणबद्ध करना।
 - (vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।
- (viii) क्षेत्रकों के विरुध हुनु निवार रूप में, ऐने विरुध को सहायता प्रदान करने में विलीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा स्नावस्थक नीलियत उपायों को सिकारिण करना ।
 - (iz) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

- 4. दल की बैठकों के सम्बन्ध म टीम के सदस्यों के याज्ञा मते/मंहगाई भक्ते का व्यय सरकारी सदस्यों के मामले में सबस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा बहुन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-मरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा बहुन किया जाएगा।
- 5. योजना क्ल के सम्बन्ध में कोई भी पत्नाचार सलाह-कार (कृषि) योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक केन्नीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-संचित्र हैं।
- 6. योजना इल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी संतिम रिपोर्ट कृषि जलवायनिक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टी/जिला परिच्छेदिका एकं अन्य आंकड़ों, की सैयारी की शर्ती के अनुसार सींपेगा।

आवैश

आदेश विया जाता है कि इस संकर्त की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/एवं त्रिभागों को संप्रेषित की जाए।

2 यह भी आदेश वियाजाता है कि सामान्य सुवनार्थ, संकरणका प्रकाशन, भारत के राजपत में कराया जाए।

> एस॰ एन॰ यह्योचींशरी निदेशक (प्रणासन)

> > अध्यक्ष

. संकल्प

सं० नयू-11012 2/97-98-ए० आर० पी० यू०-भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए गुजरात के
मेदान एवं पर्वेतीय क्षेत्र(जोन-XIII) से सम्बन्धित गोजना टीम
को योजना आयोग विल्ली के ग्रुवि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना
यूनिट और अहमवाबाद में इसके यूनिट को
सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। बित्तीय
वर्ष (1997-2002) तक नीवी पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रुवि
जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी
गई है।

पुनर्गठित टीम की संरचना निस्नानुसार होगी:

 डां० सी० एच० राणा, ्डिप कुलपति, गुजरात झृषि विश्वविद्यालय, ्सरदार कृषि नग्र, जिला-जनासकांथा-385506 ।

	24)	1998 (414.4, 1919) - END. 4—446 1
2-16. (i) जीन में राज्य सरकारों,		27. *जीनल आयोजना टीम के लिए सबस्य समिव
सम्रक्षेत्रसरकारों के मृषि	सदस्य	एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए० की प्रभार भी व के
उत्पादन आयुक्त/सचित्र कृषि	·	कार्यकर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना
्र अार उद्यान कृषि ।		टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र
 (ii) जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र के मरकारों के सिचन, पशुपासन। 	सदस्य	के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेड०पी०टी० कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके
(iii) जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र मरकारों के सक्षिव, मछली पालन ।	सदस्य	विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होता चाहिए जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेसु ,सिक्रय रूप से कार्य कर रहा हो।
(iv) जोन में राज्य सरकारों,	सदस्य	3 आयोजना टीम के विचारार्थ निषय निम्नानुसार है:
संघ क्षेत्र सरकारों के समिव,		
सिचाई और कमान क्षेत्र ।		(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/
(v) जोन में राज्य सरकारो,	सदस्य	प्रचालनीकरण केलिए योजना आयोग्√राज्य सरकार
(४) जान न राज्य सरकारा, संघ क्षेत्र सरकारों के बनों	राषरप	और जिला स्तर की अवैकाओं के अनुसार कृषि
		जलवायु जीनल आयोजना कार्य को सहायता देने
सदस्य के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक । ोन में आने वाले राज्य एवं संघ क्षेत्र		के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और आँर उन्हें मिलाना।
(i) गुजरात		
		(i¹) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना
(ii) दादरा एवं नगर हवेली संब क्षेत्र	,	तथा उपक्षेत्रोधकरण एवं कृषि जलवायविक आधार
(i¡i) दमन एवं दीव संघ क्षेत्र		पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य
 जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि विकास बैक के प्रतिनिधि 	्रसषस्य	प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयम के निर्णय मे मदद करना।
 एन०ए० बी०ए० आर० खी० (नाबार्ष) का सदस्य प्रतिनिधि 	सवस्य	(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन एवं अस्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रोद्यौगिकी ने
 *क्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि 	सदस्य	सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि -जलवायिक
 मोजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि 	सदस्य	क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आए०पो०) आक ड़ों विनिविष्ट किया जायेगा ।
 आई०सी०ए०आर मुख्यालय, नई विस्ली का प्रतिनिधि 	सदस्य /	(iv) क्षेद्वो एवं उपक्षेत्रों हेतु फस ल उगाने के तरीके (क्रोंपिंग पेटर्नस) निकालना एवं सुझावा।
 कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधि 	सदस्य	(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के
		सम्बन्ध में सिकारिश करना।
 जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि 	संबस्य	(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि
 पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि 	सदस्य	(5 वर्ष) तथा साथ ही हाथ सम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) को उपयुक्त म्कीमों कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनको सिकारिश करना; ऐसे प्रस्तायों
5. वजर भूमि विकास विभाग,	स दस्य	समय को चरणबद्ध करना।
भारत सरकार का प्रतिनिधि)1 4 2 4	(Vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का
6. पर्श पालन एवं डेयरी भारत सरकार का प्रतिनिधि	संदस्य	उत्तरवायित्व लेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।
		•

- (viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में ऐसे विकास की सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की मुमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिकारिश करना।
 - (ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी पहलू पर विचार करना।
- 4. दल की बैठकों के संबंध में टीम के सदस्यों के याजा भ ते/महंगाई भत्ते का व्ययः हिर्देकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंध्रीलय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा बहुन किया जायेगा तका योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग को संबोधित किया जा सकता है जो क्रुंचि-जलवायविक क्षेत्रीय परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सिषव हैं।
- 6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेत् रिपोटौं/जिला परिचारिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शतीं के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-लिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागी को प्रेषित की. जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ तंकल्प का प्रकाशन, भारत सरकार के राजपत में कराया जाये।

> एस० एन० ब्रह्मोचीधरी. निदेशक (प्रशासन)

संकस्प

सं ० म्यू-11912 / 97-98ए०आर० पी० यू०-भारत सरकार के दिनांक जून, 1988 के संकल्प सं० एम--13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पश्चिमी गुष्क शेख (जोन-XIV) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग, दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुन-गंठित किया जाता है वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौदी पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी देवी गई है।

2. पुनर्गंठित टीम की संरचना निम्नामुसार होगी: 1. डॉ० आर० के० पटेल, अध्यक्ष उपक्षपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334001 2-6. (i) राजस्थान राज्य सरकार का कृषि सदस्य उत्पादन आयुक्त/सचिव, कृषि और 🧸 उद्यान कृषि (ii) राजस्थान सरकार का सचिक, सवस्य पशुपालन (jii) राजस्थान सरकारका सचिव, सदस्य मछली पालन (iv) राजस्थान सरकार का सचिव, संबस्य सिंचाई और कमीन क्षेत्र सदस्य (v) राजस्थान सरकार के बनों के मदस्य प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक जोन में आने वाले राज्य एवं संघ क्षेत्र (1) राजस्थान 7. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-सदस्य विकास वैक के प्रतिनिधि एन ० ए० बी० ए० आर० बी० (नाबाई) का सदस्य सदस्य प्रतिनिधि 9. अक्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों सवस्य के प्रतिनिधि 10. योजना आयोग, भारत सरकार सदस्य का प्रतिनिधि 11. आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, सदस्य नई दिल्ली का प्रतिनिधि 12. कृषि और सहकारिता विभाग, संबस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि 13. जल संसाधन मंत्रालय, सबस्य मारत सरकार का प्रतिनिधि 14. पर्यावरण और वन मंत्रालय, सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि 15. बंजर भूमि विकास विभाग, सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि 16. पशु पालन एवं डेयरी, सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधि

17. *जोनल आयोजना टीम हेत् सदस्य-

सचित्र

सवस्य-सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य-सचिव एवं गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० आर०पी० के कार्य कर रहे निश्वित्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथ्या कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना भायोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलता-पूर्वक जेष्ठ०पी०टी० कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके थिवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है, गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सिक्षय रूप से कार्य कर रहा हो।

आयोजना टीम के जिचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- (i) इटि जलवाय क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानी-करण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/ राज्य संग्कार और जिला स्तर की अवेक्षाओं के अनुसार इटि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत स्चना य आंकड़े एकत करना और उन्हें मिलाना।
- (ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उन्नेजोशकरण एवं कृषि-जलवायिक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।
- (iii) मृद्या सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगामें के तरीके (फ्रोपिंग पैट्रम) प्रमुक्षन एवं अन्य क्रोक्तंगिक क्षेत्रक तथा ६न क्षेत्रकों की प्रोग्नीगि-कीय सम्भावनायों एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि—जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आए० प्री०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- (iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीकें (ऋोपिंग पट्टन्स) निकालना एवं सुझाना।
- (v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गति-विधियों के सम्बन्ध में सिफारिण करना।
- (vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यभिक अवधि (क्ष्यर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 घर्ष) की उपयुक्त एकीमों कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनक्की सिफारिश करना; ऐसे प्रस्ताशों के समय को चरणश्रद्ध करना।
- (vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।
- (viii) क्षेत्रकों के विकास हैतु विशेष रूप में ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में विक्षीय संस्थाओं की भूमिका की जांव करना सथा आवश्यक नीति-गत उपायों की सिफारिश करना।

- (ix) इसके कार्य एवं उद्देषयों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहल पर विकार करना ।
- इन की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यास्रा भने/महगाई भने का व्यय, के गामले में भवस्य: 3 अपने विभाग/ मंत्रालय/राज्य गरकार/विश्वहिद्यालय वहन क्षांरा किया जायेगा तथा योष्ट्रहा दल सदस्यों के मामले में 🐃 व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 5. योजना रच के सम्बन्ध में कोई भी पत्नाचार सलाह-कार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सिवव हैं।
- 6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तया वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टी/जिया परिष्के दिका एवं अन्य अंकड़ों की तैयारी की शर्ती के अनुसार सौंपेगा।

त्रादेश

आदेश दिया जाता है कि इप 'संकल्प की एक-एक प्रतिलिप बोजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित संज्ञालयों एवं विभागों को संबेधित की जाए।

2. पह भी श्रादेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकारप का प्रकाशन, भारत के राजभन्न में काया जाए।

> एस० एन० अह्योचीधरी, निदेशक (प्रणासन)

> > संदस्य

मक्त-प

भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए प्रायद्वीग क्षेत्र (जोन-15) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जनवायु क्षेत्रीय प्रायोजना यूनिट और अहमदाबाद में उसके यूनिट को सहायता देशे के लिए पुतर्गटिन किया जाता है। विलीव नर्ग (1997-2002) तक नौवीं पंचवपींग योजना हैतु अधि जलवायु क्षेत्रीय प्रायोजना परियोजना को मंजूरी दे टी गई है।

- 2. पनगॅित टीम की संरक्ता निम्तानुसार होगी।
- डा० जी० वी० सिंह, उप महानिदेशकः श्रध्यक्ष भारतीय कृपि श्रनुसंघान परिषद, कृषि भवत, नई दिस्ली--110001
- 2---11 (i) जोत में संघ क्षेत्रों के भ्रुषि उत्पादन आयुवत/सर्जिक कृषि और उद्यान कृषि

(ii)	जोन में संघ क्षेत्रों के मचिन	
	पश्रालन	सदस्य
(iii)	जोन में संघ क्षेत्रों के समित्र,	्यिकस्य
	गलभी पालन	
(\mathbf{v})	जीन में संय केंद्रों के सचिक.	-
	सिचाई और कमान क्षेत्र	मद-य
(vi)	जीन में संघ ज़िलों के वनों क	
	प्रधान चीफ/संख्य संरक्षक	मद्≠प

जोन में भ्राने वाले संघ क्षेत्र

- (i) अण्डमान निकोबार द्वीप समह
- (ii) लक्ष्यद्वीप
- 12. जीन में ब्राने वाले राज्यों के सहकारी भूमि -विकास वैफ के प्रतिनिधिः य

'13 एन० ए० बी० ए० श्रार० डी० (नावार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि

्र14. *<mark>श्रेत में संबंधित गैर मण्कारी— संगठनों के</mark> प्रतिनिधि

सदस्य

सदम्य

स दश्य

- 15. योजना धायोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि
- াঁও, স্নাই০ सी० ए० গ্নাহ০, मुख्याश्रय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि सदस्य
- 17. कृषि और सहकारिता विभाग भारत , सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

18. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का सदस्य

19. पर्यावरण और वन मंत्रालयं, भारत संस्कार

का प्रतिनिधि सब १० जन्म प्राप्ति विकास विभाग भारत सरकार

20 बजर भूमि विकास विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

21. पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

22. डा॰ ए० के० बंबोपाध्याय. निद्मक केन्द्रीय
, इपि प्रनुसंधान संस्थापना, घण्डमान एव
निकोबार द्वीप समूह. पोर्ट क्लेयर. पिन
कोड-744101। सदस्य-पिन

. *गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को आयोजना टीम के अध्यक्ष हारा योजना आयोग नई दिल्ली कि सूचित करने हुए नामित किया जाना है। यह गैर-सरकारी संगठन एसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहा हो।

- श्रायोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नाम्सार है:
- (1) कृषि जनवाय क्षेत्रीय श्रायोजना के संप्यानीकरण/ श्रवालनीकरण के लिए योजना श्रायोग/राज्य

सरकार और जिला स्तर की श्र**ेक्षाओं के श्रनुसार** कृषि जनावायु जीनल श्रायोजना कार्य की संहायता देने के लिए संगत सूचना व श्रांकडे एकत करना जीर तन्हें मिलासा ।

- (2) पूर्व में प्राप्त किए गए श्रांकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक श्राधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी श्रन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/जन्मयन के निर्णय में गदद करना।
- (3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फमल उगाने के तरीके (कोदिंग पैटर्न) पशुधन एवं श्रन्थ धार्मांपक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रोधोगिकीय संभावनाएं एवं इनके पर्यादरणीय, समाजिक एवं श्राधिक कारकों के संबंध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए० सी० श्रार० पी०) श्रांकड़ों को विनिद्धिट किया जाएगा।
- (4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्षोपिंग पैटर्नस्) निकालना एवं सुझाना ।
- (5) गैर-फसल कृपि, वानिकी, पणुपालन एवं क्षेत्र-विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गति विधियों के संबंध में सिफारिशें करना।
- (6) क्षेत्र के कृषि संबंधी विकास हेतु माध्यमिक ग्रवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी ग्रवधि (10 मे 15 वर्ष) की उत्थुवन स्कीमी/कार्यक्रमी को तैयार करना तथा उनकी मिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।
- (7) इसके उद्देश्य के लिए ग्रावश्यक ग्रध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि ग्रावश्यक हो तो उन्हें भ्रधिकृत कराना ।
- (8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की मिफारिक करना ।
- (9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहल पर विचार करना।

4 दल की बैठकों के संबंध में, टीम के सदस्यों के याता भक्ते/मंड्गाई भन्ने का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामने में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्व—विद्यालय द्वारा वड्न किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-- सरकारी सदस्यों के मामने में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वडन किया जाएगा।

4-421 GI/97

5 योजना दल के सुवंत्र में कोई भी गवावार सनाह-कार (कृषि), योजना आयोग को संगोधित विभा जा सकता है जो कृषि—जनवारिक धेलीय जीजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-मिचब हैं।

6. योजना क्य अन्तरिम रिपोर्ड जैसे और जब अविश्यक हो, सींप मकता है तथा यह अवसी अंतिम रिपोर्ट कृषि— जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टी/लिखा परिचर्छेदिका एवं अन्य आंकशों, की तैयारी की कार्ती के अनुसार सींपेगा।

श्रादेश

सारेण दिया जाना है कि इस संकल्प की एया-एक प्रति-विभि गोचना दन के सध्यक्ष एवं लक्स्यों, धारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी भस्योधित मेत्रालयों एवं विभागों को संप्रेपित की जाए।

यह, भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ,
 संकल का प्रकाशन, भारत के राज्यत में कराया जाए।

एय० एन० ब्रह्मोचौधरी निदेशकः (प्रणासन)

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 4th July 1997

RESOLUTION

No. O 11012/2/97-98 ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Acri dated 3rd June, 1988 the Planning Team for Eastern Himalayan Region (Zone-II) is re-constituted for giving support to Aero-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad Ayro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:--

Chai: man

 Dr. A. K. Mukhopadhyav. Vice-Chancellor, Assam Agricultural University, Jorhat. Assam.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Mombers

- 2, Vice-Chancellor, BCKV, West Bengal.
- 3. Vice Chancellor, Control Agricultural University, Imphal, Manipur.
 4—48.
 - (i) Agricultural Production Commissioner/Secretarles, Agri. & Hertlenlture, Govts, of the States in the Zone.
- Secretaries, Animal Husbandev, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Initiation & Command Arm, Govis, of the States in the Zone.
- (v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts, of States in the Zono

STATES IN THE CONE

- (i) Assam (Dispur)
- (li) West Bengal (Calcutta)
- (iii) Arunachal Piladesh (Itanigae)
- (iv) Manipur (Imphal)
- (v) Meghalaya (Shillong)
- (vi) Misoram (Aizawal),
- (vli) Nagaland (Kohima)
- (viii) Tripura (Agartala)
- (ix) Sikkim (Gangtok).

Members

- 49. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 50. Representative of NABARD.
- Representative of concerned NGOs in the region. Shri Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Asbram PO Chuchyinilong, Dist. Mokokchung, Nagaland.
- 52. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 53. Representative of ICAR, Head Quarter, New Delhi.
- 54. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOL
- 55. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI,
- 59. Member-Secretary for the Zonal Planning Team is to be nominated by Chairman of Planning Team from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently, under intimation to Planning Commission, New Delhi.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:--
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Acro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adhertment/undating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Associanatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground whiter, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend (cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with repard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.

- (vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
- (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- , 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution 1: communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2, Ordered also that the Resolution be published in the

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

The 14th July 1997

- No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Himalayan Region (Zone-I) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows

Chairman

 Dr. R.P.S. Tyagi, Vice-Chancellor Himachal Pradesh Krishi Vishwavidalay Palampur, Himachai Pradesh.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- 2. Dr. Y. S. Parmar, University of Horticulture & Forestry, (via conchehat), Solan, Himachar Pradesh.
- 3. (i) Shere Kashmir University of Agricultural Sciences, Shalimar Campus, Srinagar-191001.
 - (ii) 45-B, Gandhi Nagar, Jammu Tawi, Jammu-12004.
- Dean College of Hill Agriculture and Forestry, Rani Chauri Campus of GBPUAT (Nominee of Vice-Chancellor, GBPUAT, Pant Nagar, Nanital).

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.
- (ii) Scoretaries, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

- (i) Jammu and Kashmir
- (ii) Himachal Pladesh.
- (iii) Uttar Pradesh.

Members

- Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 21. Representative of NABARD.
- 22. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 23. Representative of Planning Commission, Government of India.
- 24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 25. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India,
- Representative of '4inisay of Environment & Forests, Govt, of India.
- Representative of Department of Wasteland Dev., Govt. of India.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Durrying, GOI.

- 30. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

 Member-Secretary and NGO member are to be nominated by Chairman of Planning feam under intimation to Planning Commission, New Deim. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capatinity and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/Stat. Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine Cata collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground whiter, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors,

- technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
- (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
- (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
- (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
- (ix) To consider any other aspect relevant to its work, and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the nou-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER &

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of Silate Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Gove of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 31d June, 1988, the Planning Team for Lower Gangetic Plains Region (Zone-III) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

Chairman

 Dr. M. G. Som, Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalayla (BCKV.), Mohanpur, Distt. Nadia, West Bengal.

Members

2--6

(i) Agricultural Production (.... y, Agri. & Horticulture, Govt.

- (ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of West Bengal,
- (iii) Secretary, Fisheries, Govt. of West Bengal.
- (iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govt. . West Bengal.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, Govt. of West Bengal.

STATE IN THE ZONE

(i) West Bengal.

Members

- 7, Representative of Cooperative Land Development Bank of the State in the Zone.
- 8. Representative of NABARD,
- 9. Representative of concerned NGOs in the region.
- 10. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 14. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Dev., Govt. of India.
- Rep. esentative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOL
- 17. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

Member-Secretary

Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO chould be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are an tollows:---
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground wlater, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (v) To device and recommend cropping patterns for the region on sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities subable for the tegion.

- (vi) To formulate and recommend suitable schemes/
 programmes for the agricultural development of
 the region in the medium (5 years) as well as long
 term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Cor.mission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports, district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Middle Gangetic Plains Region (Zone-IV) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission—Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

Chairman'

Dr. K. S. Chauhan, Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural University, Pusa, Distt. Samustipur, Bihar-848125.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

Narendra Dev Unversity of Agriculture and Technology, Kumarganj, Distt. Faizabad, UP-224001.

3. _12

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone

- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

- (i) Bihar
- (ii) Uttar Pradesh.

Members

- 13. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 14. Representative of NABARD,
- 15. "Representative of concerned NGOs in the region.
- Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 17. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Dellai.
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, (WB).

Member-Secretary

23. Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as por requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant required for operational planning on Agro-climatic
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (1v) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-moressing activities rultable for the region

- (vi) To formulate and recommend suitable schemes/
 programmes for the agricultural development of
 the region in the medium (5 years) as well as long
 term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in par-ticular the role of financial institutions in supporting such development.
- (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

> S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU,—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, the Plenning Team for Upper Gangetic Plains Region (Zonc-V) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delai and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for 1Xth Five Year Plan upto financial year (1997—2002)

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :-

Chairman

Dr. I.P.S. Yadav, Vice-Chancellor, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kan-pur (UP)-208002.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology (GBPUAT), Pant Nagar, Dist. Nanital,

- (1) Agricultural Production Commissioners/Secretary, Agri. & Horticulture, Govt. of Uttar Pradesh.
- (ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of Uttar Pradesh.
- (Hi) Secretary, Fisherice, Govt. of Uttar Fradesh.

- (iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govt. of Uttar Pradesh.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, of the Govt. of U.P.

STATES IN THE ZONE

Members

- (i) Uttar Pradesh.
- 8. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 9. Representative of NABARD.
- 10. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 11. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 12. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 13. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- 14. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- 15. Representative of Ministry of Environment & Forests. Govt. of India.
- 16. Representative of Department of Wasteland Development, GCI.
- 17. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOL.

Member-Secretary

18. *Member-Secretary for the Zonal Planning Jeam.

"Member-Secretary and 'NGO are to be nominated by Chairman of Planning Team under in-timation to Planning Commission, New Delhi. Mem-ber-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his dis-cretion depending on capability and availability of retion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the ducision or adjustment/updating on sub-re-gionalisation and any other relevant information. required for operational planning on Agro-climatic
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pat-tern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long tern, livestock, fisheries and other relevant rectore, posal,

- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the cectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
- (ix) To consider any other espect relevant to its work, and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong land by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agraclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Tesim may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India:

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 the Planting Team of Trans Gaugetic Plains Region (Zone-VI) is re-constituted for giving support to Agroclimatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

Chairman

 Dr. Amariit Singh Khera, Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhlana.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- 2. Chaudhary Charan Singh Agricultural University, Histor, Haryana-125004.
- 3. Rajarthan Agricultural University, Bikaner-334000.

4-28.

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govis. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Rusbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Arca, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts, of States in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

- (i) Punjab
- (ii) Haryana
- fine Rajasthan
- (iv) UT of Chandiganti
- (v) National Capital Territory of Delhi.
- 29. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone

Members

- 30, Representative of NABARD
- 31. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 32. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 33. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 34. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- 35t Representative of the Ministry of Water Resources, Govt, of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

39. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team:

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi, Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on canability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Apro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

- (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institution: in supporting such development.
- (ix) To consider any other aspect, relevant to as Work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of Sate Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govi. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Eastern Plateau and Hill Region (Zone-VII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

* Chairman

 Dr. K. Pradhan, Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar-751003.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, Distt. Nadia, West Bengal.
- 3. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (MP,
- Birsa Agricultural University, Kanke, Ranchi, Bihar-834004.
- 5. Punjabras Krishi Vidyapeeth, Akola, Maharashtra.
- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Hordiculture, Govts. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries Fisheries, Govts of the States in the Zone,

- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Covts of States in the Zone

STATES IN THE ZONE

- (i) Orissa
- (ii) West Bengal
- (iii) Madhya Pradesh
- (iv) Bihar
- (v) Maharashtra',

Members

- 31. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 32. Representative of NABARD.
- 33. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 34. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 35. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 36. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- 37. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- 38. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- 39. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Director, Padmaja Nhidu Himalayan Zoological Park. Darjeeling, WB.

Member-Secretary

41. Dr. B. Bhuyan, Prof. & Head Agricultural Economics, Orksa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar-751003,

*NGO are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission. New Delhi. NGO should be one be'ively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows, :--
 - (1) To collect and collate relevant information and data to support Apro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of distinguishment/undating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground whiter cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with record to non-crop agriculture, forestry, animal husbanday and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned studies required for its objectives.

- (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
- (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong kind by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Advisor (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per teams and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

- Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Term, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.
- 2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Central Plateau and Hill Region (Zone-VIII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:

Chairman

 Dr. Punjab Singh, Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya (JNKVV), Jabalpur (MP)-482004.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- 2. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334001.
- Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology Kanpur-208002.

4--18.

- Agricultural Production Commissioner/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govis. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govte. of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries. Irrigation & Command Aren, Govts. of the States in the Zone,
- (v) Principle Chief/Chief Conservator of Forests, of the Govts, of States in the Zone,

STATES IN THE ZONE

- (i) Madhya Pradesh
- (ii) Uttar Pradesh
- (iii) Rajasthan
- 19. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

Members

- 20. Representative of NABARD.
- 21. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 22. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 23. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- 25. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

- 29. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

 *Member Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under ir timation to Planning Commission, New Delhi. Menber-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discrition depending on capability and availability person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :— $^{\bullet}$
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per regulirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalist tion/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes, programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

- (ix) To consider any other aspect relevant to its work, and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong tand by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gezette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govif India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Plateau and Hill Region (Zone-IX) is re-constituted for giving suport to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

Chairman

 Dr. Y. S. Nerker, Vice-Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (MPKV), Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashira-413722.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth (PKV), Krishi Nagar, Akola. Maharashtra-444104.
- Jawahar Lai Nohru Krishi Vishwavidyalaya (JNKV), Jabalpur (MP) Pin-482004.
- 4. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-33400.

5-19.

- (i) Agricultural Production Commissione /Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts: of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone:
- (iv) Secretarles, Irrigation & Command, Area, Govts, of the States in the Zone.
- (v) Principle Chlof/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

- (i) Maharashtra
- (ii) Madhya Pradosh
- (iii) Rajasthan

- 20. Representative of Coperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 21. Representative of NABARD.
- 22. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 23. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- 29. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

- 30. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.
 - *Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalistion/operationalisation of Agro-climatic Regions-Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on subgionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimat.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of seil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Tenin in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who it Member-Secretary of the High Level Committee on Agro... Climatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shail submit its final report is per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated, to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministrics and Departments of Sinte Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Feam for Southern Pateau and Hill Region (Zone-X) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regionel Flanning Unit of Planning Commission-Delbi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:—

Chairman

1. Dr. P. Mahadevappa, Vice-Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad (Karnataka).

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad; Pin-500030.
- 3. Tamill Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.
- 4. University of Agricultural Sciences, Bangalore, Karnataka-560065.

5---19.

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts, of the States in the Zone.
- (ii) Ser is, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts, of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

- (i) Andhra Pradesh
- (ii) Karnataka
- (iii) Tamil Nadu
- 20. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 21. Representative of NABARD.
- 22. *Representative of concerned NGOs in the region.

- 23. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- 28. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

30, *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:--
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroctimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic tactors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Advisor (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of greparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govof India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for East Coast Plains and Hill Region (Zone-XI) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad, Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:-

Chairman

1. Dr. A. Abdul Karim, Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- 2. Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad, Pin-500030.
- 3. Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar-751003.

4-23

- Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, Jarigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone,

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

- (i) Andhra Pradesh
- (ii) Orissa
- (iii) Tamil Nadu
- (iv) UT of Pondicherry
- 24. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 25. Representative of NABARD.
- 26. *Representative of concerned NGOs in the region.

- 27. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 28. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt, of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

- 34. *Member-Secretary for Zonal Planning Team.

 *Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University *Mendling the work of ACRP or Head of Agre-conomic Research Centre, according to his discrition depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development, of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional's Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other televant information required for operational planning on Agroclimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-cropagnizulture, forestry, animal husbandry land agro-processing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/
 programmes for the agricultural development of
 the region in the medium (5 years) as well as long
 term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake land if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who

- is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY'
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team of West Coast Plains and Ghat Region (Zone-XII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:--

Chairman

 Dr. A. G. Sawant, Vice Chancellot, Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli Distt. Ratnagiri, Maharashtra-415712.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

- Kerala Agricultural University, Vellanikkara, Trichur-680654.
- University of Agricultural Sciences. Dharwad, Karnataka.
- Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.

5---3-1.

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govis. of the States in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts, of the States in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts, of the States in the Zone.
- (iv) Secretaries, farigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts, of States in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

- (i) Kerala
- (ii) Tamil Nadu
- (iii) Kacnataka
- (iv) Maharashtra
- (v) Goa
- (vi) Pondicherry (Muhe)

Members

- 35. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone
- 36. Representative of NABARD
- 37. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 38. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 39. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 40. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- 42. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, GOI.
- 44. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

- 45. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

 *Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discrition depending on capability and javailability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development, of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State. Government and District Level, for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground whiter, cropping pattern, livestock, fishenes and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ÓRDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

 2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

> S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govi. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Gujarat Plains and Hill Region (Zone-XIII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delni and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:--

Chairman

Dr. C. H. Rana, Vice-Chancellor, Gujarat Agricultural University Sardar Krushi Nagar, Distt. Banaskantha-385506.

Members

2-16,

- Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govt. of the States in the the UTs in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govt. of the State and UTs in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the State and UTs in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts, of the State and UTs in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conscivator of Forest, of the Govt. of State and UTs in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

- (i) Gujarat
- (ii) U. Territory of Dadra & Nagar Haveli
- (iii) U. Territory of Daman & Diu.
- 17. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 18. Representative of NABARD.
- 19. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 20. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

- 21. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 22. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India.
- 23. Representative of the Ministry of Water Resources, Govi. of India.
- 24. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- 25. Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.
- 26. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, Govt, dt India.

- 27. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

 *Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:-
 - (1) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.
 - (iii) ACRP plunning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend tropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its cylectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong (and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Dry Region (Zone-XIV) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for 1Xth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:-

Chairmar

1. Dr. R. K. Patel, Vice-Chancellor, Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334001.

Members

2---6.

- (i) Agricultural Production Commissioner/Secretary, Agri. & Horticulture, Govt. of Rajasthan.
- (ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan.
- (iii) Secretary, Fisheries, Govt. of Rajasthan.
- (iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govi. of Rajasthan.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, cf. the Govt. of Rajasthan.

STATE IN THE ZONE

(i) Rajasthan

Members

- 7. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.
- 8. Representative of NABARD.
- 9. *Representative of concerned NGOs in the region.
- Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 11. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- 12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India.
- Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.
- Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, (WB).

Member-Secretary

- 17. *Member-Secretary for the Zonal Planning Term.
 - *Member-Secretary and NGO Member, are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi, from concerned department of University handling the work of ACRP of Head of Agro-Economic Research Contre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.
- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:—
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating gionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of roil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend bropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities uitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recomm 1 policy measures requircd for the development or the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Teom in connection with the ricetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP

OLDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gereite of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU. -In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for The Island Region (Zone-XV) is re-constituted for giving support to 'Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan unto tinancial year (1997—2002)

2. The composition of the re-constituted team will be as follows:---

Chairman

 Dr. G. B. Singh, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, Krishl Bhavan, New Delhi-110001.

Members

2 -- 11

- (i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, of the UTs in the Zone.
- (ii) Secretaries, Animal Husbandry, of the UTs in the Zone.
- (iii) Secretaries, Fisheries, of the UTs in the Zone.
- (iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, of the UTs in the Zone.
- (v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, of the UTs in the Zone.

UTs IN THE ZONE

- (i) Andaman, Nicobar Island
- (ii) Lakshadweop

Members

- Representative of Cooperative Land Development Bank of the UT in the Zone.
- 13. Representative of NABARD.
- 14. *Representative of concerned NGOs in the region.
- 15. Representative of Planning Commission, Govt. of India.
- 16. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.
- Representative of the Department of Agriculture & Cooperation. Govt. of India.
- 18. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.
- 19. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.
- 20. Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.
- 21. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, Govt. of India.

Member Secretary

- Dr. A. K. Bandyopadyay, Director Central Agricultural Research Institute for Andaman and Nicobar Group of Island, Port Blair-744101.
- *NGO member is to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. NGO should be one actively working for development of Agriculture, and Allied areas in the Zone.

- 3. The terms of reference of the Planning Team are as follows:
 - (i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and Distric' Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.
 - (ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.
 - (iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground whater, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environment, social and economic factors to these sectors.
 - (iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.
 - (v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agroprocessing activities suitable for the region.
 - (vi) To formulate and recommend suitable schemes/ programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.
 - (vii) To undertake and if necessary get commissioned, stadies required for its objectives.
 - (viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.
 - (ix) To consider any other aspect relevant to its works and objectives.
- 4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will he home in respect of official members by the Department Ministries/State Government/Universities to which the members belong band by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.
- 5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri). Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agroclimatic Regional Planning Project.
- 6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shell submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairmon and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution by published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY Director (Administration)